Government that some influential persons are purchasing plots in the aforesaid area; and

(e) what action has been taken to prevent illegal sale/colonisation/construction and whether Government propose to put up a special picket to keep watch over the area?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) As reported by DDA, the title of 46 bighas 9 biswas of land bearing Khasra No. 166 of village Ladho Sarai is sub-judice in the High Court of Delhi.

(b) The prescribed land use of the land is "recreational".

(c) and (d) The Deputy Commissioner, Delhi has reported that unauthorised development and sale/purchase of the land is taking place.

(e) The DDA has issued a public notice warning the public that the sale/purchase of this piece of land is illegal till the matter is finalised by the Competent court. It is also keeping a watch on the area.

मसालों के लिए समर्थन-मूल्य

*260. **श्री कैलाश नारायण सारंग**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों को लहसुन, धनिया और मिर्च आदि मसालों की फसलों के लिए उपयुक्त मूल्य नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य निर्धारित करने पर विचार करेगी, जैसाकि खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों के संबंध में किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) वर्ष 1993 में सामान्यतया: मसालों तथा विशेषकर लहसुन, धनिया और लाल मिर्च के थोक मूल्यों में समझ और अन्तराल की दृष्टि से उतार-चढ़ाव आया है जैसाकि व्यावहारिक रूप से सभी कृषि जिंसों के मामले में हुआ है। यह उतार-चढ़ाव मुख्यतया इन जिंसों की मांग और आपूर्ति, विदेशी उत्पादन तथा निर्यात में अंतर के कारण आया है। यद्यपि 1993 में लाल मिर्च के थोक मूल्य नरम रहे, तथापि लहसुन और धनिया के थोक मूल्य कुल मिलाकर 1992 के स्तर से अधिक रहे।

(ख) और (ग) विभिन्न फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत लाने के प्रश्न को कृषि लागत और मूल्य आयोग से परामर्श करते हुए लगातार समीक्षा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में शामिल की जाने वाली फसलों के बारे में निर्णय लेते समय स्थानिक उत्पादन वाली और देश में व्यापक रूप से उगायी जाने वाली फसलों, जल्द खराब होने वाली तथा जल्द खराब न होने वाली कृषि जिंसों और देश के कुल फसल उत्पादन में योगदान देने वाली फसलों में अन्तर करने का प्रयास किया जाता है। मसालों के मामले में, इनमें से कोई भी मानदण्ड उन्हें न्यूनतम समर्थन योजना में शामिल किए जाने के लिए उचित नहीं ठहराता। लेकिन, यदि मूल्य अलाभकारी स्तर तक गिर जाएं तो राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर मसालों को मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है।

Role of Animal in Agricultural Operation

2249. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that animal power plays a great role in the agricultural operations of the country;

(b) whether Government have assessed the importance of animal power in agricultural operation; if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that number of animals in the country is gradually coming down;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the steps being taken to check this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) On an average a pair of bullocks is capable to manage 3 hectares. On this basis, the crop area which can be managed by 40 million pairs of bullocks is 120 M hect., out of total sown area of 150 M hect. By 2000 AD the requirement may remain the same because of better breed and better health. So number is to be maintained at existing level.

(c) No, Sir. The Cattle population according to 1982 Census was 192.45 Million and it has increased to 199.45 million in 1987.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

दालों और मसालों का उत्पादन

2250. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान